

सं. 21/70/2013-एम एंड जी

भारत सरकार

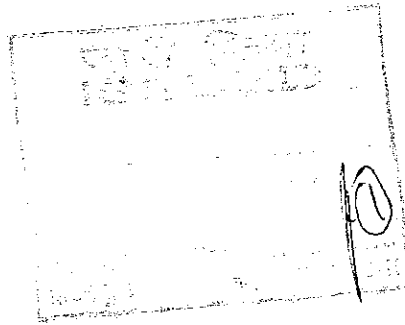
गृह मंत्रालय

एन डी सी सी-11, नई दिल्ली

दिनांक: 25 June, 2013

सेवा में,

श्री मंजीत सिंह,
46 बी/14 कृपाल नगर,
रोहतक-124001
(हरियाणा)



26/6/13

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना उपलब्ध कराना।

महोदय,

मुझे, उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक 25.02.2013 के आवेदन का उल्लेख करने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि इस केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का संबंध मांगी गई सूचना के उस भाग से है जो बिन्दु सं. 4,5,6 तथा 11 पर है। बिन्दु-वार उत्तर निम्नलिखित है:-

बिन्दु सं. 4 तथा 6

संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है।

- (क) किसी राज्य में से उसका राज्यक्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी;
- (ख) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी;
- (ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी;
- (घ) किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तित कर सकेगी;
- (ङ) किसी राज्य के नाम में परिवर्तित कर सकेगी;

परन्तु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है वहां जब तक उस राज्य के विधान मंडल द्वारा उस पर अपने विचार, ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है अथवा प्रकट विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में स्थापित नहीं कि जाएगा।

भारत में सात संघ शासित प्रदेश हैं जो निम्न के अनुसार हैं:-

- (1) अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह

- (2) चंडीगढ़
- (3) दादरा एवं नगर हवेली
- (4) दिल्ली
- (5) दमण एवं दीव
- (6) पुडुचेरी
- (7) लक्षद्वीप

बिन्दु सं.-5 भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति ने श्री अश्विनी कुमार तथा श्री एस.सी. जैन को क्रमशः नागालैंड तथा उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया था।

बिन्दु सं.-11 भारत के संविधान की धारा 331 में यह प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति का यह मत है कि लोक सभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो वे उस समुदाय के अधिकतम दो लोगों को उक्त सदन हेतु नामित कर सकते हैं।

3. इस मामले में अपील प्राधिकारी श्री एस. सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव (सी एस), गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-11, भवन, जयसिंह रोड, नई दिल्ली हैं।

भवदीय,



(आशुतोष जैन)

निदेशक (सी एस) तथा

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

दूरभाष: 23438147

Enro - प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

3/2013 श्री श्रीनिवास प्रधान, उप सचिव (ई) तथा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, आर टी आई सैल, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके दिनांक 08.04.2013 के का. जा. सं. ए-43020/01/2013 आर टी आई के संदर्भ में।

26/4/13

1) गृह मंत्रालय ने किशन Dn/Secy/SP/DC और IAS/IPS को लाल वही लगाये की मरु किस नियमकृत और दो गई IAS/IPS लाल वही नई बना (मरु)

7) गृह सचिव को नियुक्ति के चयन किया जाता है

8) प्रस का आयर आफ डाइम के अध्यक्ष को सरकार के नियुक्त करती है

9) अवध रूप से लालवही लगाने और पर क्या कारवाई होती है

9) ग्रामिण आयोग के अध्यक्ष का चयन/नियुक्ति कैसे की जाती है

3) जब दिल्ली सरकार राज्य है, तब भी "दिल्ली पुलिस" है फिर भी दिल्ली सरकार का नियंत्रण नहीं है। अतः जांचकारी की जाए कि दिल्ली पुलिस रहने न्याय के अधीन क्या रहती गई है

10) चुनाव में समाज को रहती जाती है लगभग 30% तो आवेदी जारी है, वो तो कर दे सकती है

4) किन्द शासित प्रदेश/क्षेत्र बनाने की क्या प्रक्रिया है देश में कुल किन्द क्षेत्र है और क्या बनार जाए है

11) लोक सभा में दो तरह डाइमन नामित क्या होते हैं

5) CBI के पूर्व निदेशक अग्रणी कुमार को किस चयन प्रणाली के तहत जागवर्ड का वर्तमान बनाया गया / कार्यसूची/संसाधन/उत्तर को ओडिसा का बडगाप/त के नियुक्त किया गया / चयन प्रक्रिया की जानकारी दीजिए

12) किस चयन प्रणाली से रजिस्टर निर्मल कमा का कनाडा से उच्चासुप्त बनाया गया है

6) दो प्रान्तों की क्वार्टर डी लोडन का निर्धारण कैसे निर्धारित की जाती है एक बार पाक में पान्त हरियाणा पर भी रजिस्ट्रार आयोग मसुदा नदी का दृष्टि/नियमन को छोड़ होता है

13) सुप्रीम दस्ता लाठीचार्ज करती है / यह सीड (अवलोकनकार) पर गारंटी केनन रखे जाते हैं, वीडियो प्रती क्या नहीं करती

14) देश में सभी शाही वीरों के नाम क्या रखे जाते हैं